[Shri Jibon Roy]

power no irrigation can be undertaken. The result is that agriculture also cannot develop. Therefore, it is high time that the Government of India paid attention to this and took some steps.

They have come here to demonstrate before the Parliament House. I would request the Government of India, through the Chair and through this House, to take up the matter urgently and take some steps in this regard.

STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION ISSUED UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF MANIPUR

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): Mr. Vice-Chairman, I rise to move:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 31st December, 1993, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Manipur.

The situation in Manipur had been steadily deteriorating in the recent past. There had been serious acts of violence by insurgents even in Imphal, the capital town. The Governor of Manipur in recent reports sent to the President had given his assessment of the law and order situaiton in the State. The Governor had reported that the law and order situation in the State was grave and had the potential of getting out of control, both due to the activities of the insurgents and the on-going Naga-Kuki conflict. This conflict, which almost certainly is an extension of the NSON(I) design for domination, through ethnic cleansing, had been further accentuated by the support it received from political leaders of both the communities in furtherance of their narrow political ends.

The Governor further reported that due to the ineptitude and in-fighting in the Government, the NSON(I) had doubled its cadre strength during 1993 with two more groups infiltrating in January and June, 1993, with approximately 200 sophisticated weapons. The NSON(I) had further strengthened its links with the Meitei extremists, ULFA, HPC and the Myanmar insurgents. They have also had active support from the intelligence agencies from across the borders. The Governor had come to the conclusion that the faction ridden political parties and groups, infiltration of innsurgents into pilitical parties, ethnic conflicts and infighting, and the inept leadership had contributed to the creation of a situation making it necessary to impose President's Rule in the State. Accordingly, the Governor had recommended that a Proclamation might be issued dismissing the Ministry and keeping the State Legislative Assembly under suspended animation. According to the Governor, a period of cooling off would not only minimise the influence of political leaders with questionable antecedents, but could also help inencouraging an alternative and better leadership to emerge.

The Union Government had been regularly monitoring the situation in Manipur and additional Central Para-military Forces were deployed and the Army also inducted.

The Union Government considered the reports of the Governor and the situation in Manipur and decided to recommend to the President of India to issued a Proclamation under articel 356 of the Constitution and keep the Legislative Assembly under suspended animation. The Proclamation under article 356 of the Constitution was issued by the President on 31st December, 1993.

In view of the circumstances, which I have just explained, I commend, Sir, that the Proclamation issued on 31st December, 1993 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Manipur be approved by this august House.

The question was proposed.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): मणिपुर के स्टेच्युरी रेज़ोल्यूशन पर मैंने नोटिस आफ डिसएप्रूवल दिया था, उसका क्या हुआ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Okay, I will check it up. .....Actually, your notice has been rejected because there is no convention of moving any resolution disapproving a Proclamation.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: बराबर होता है, इस हाउस में बराबर हुआ है। रिवोकेशन के लिए बराबर हुआ है, डिस्कस हुआ है।

ऐसा कोई कन्वेशन था ही नहीं। Both have been discussed together.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Sir, may I make a submission? A number of times such kind of notices were there in the House disapproving Presidential Proclamaitons by the Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTAY RAZI): I will check it up later and let you know.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उस पर अभी रूलिंग होनी चाहिए। इसलिए कि टेक-अप लेटर कैसे हो सकता है। .....**(व्यवधान)**

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I think it should be resolved now.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think it was on some technical grounds. Let me check it up from the Secretariat what the reason for the rejection was.

SHRI MENTAY PADMA-NABHAM: You also know that this convention is very much there.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): It may be some problem with the wording. It has been rejected on some technical grounds. I have asked the Secretariat to let me know the exact position.

...(Interruptions)...

SHRI MENTAY PADMA-NABHAM: May be that is a different proposition, but *...(Interruption)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): It might not have been in the proper form.

SHRI MENTAY PADMA-NABHAM: That is a different thing—I am not disputing it—but, Sir, your observation that there is no convention in this House for that kind of a motion is not correct.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I have gathered the information on how your motion was rejected. Previously there had been that practice, but later on there were some objections on the floor of the House itself, and the matter was considered by the Chairman. Now that practice has been done away with, and disapproval of ordinances has been allowed. Your application was not coming under that new convention, and it was rejected.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1993 को जारी की गई राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना को सदन के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। मैं अपने दल की ओर से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां मणिपुर मे पैदा हो गई थी और जिस तरह संवैधानिक मशीनरी वहां बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उन परिस्थितियों के मद्देनजर वह मेरा दल जो कि आम तौर पर धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की कभी भी वकालत नहीं करता, उसे भी आगे बढ़कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग करनी पड़ी थी। हमने स्वयं चाहा था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे। नागा और कुकी संघर्ष मणिपुर में कुछ नया नहीं था। लेकिन जब से दोरेन्द्र सिंह की सरकार आई थी तब से यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। यदि एक वर्ष का आंकड़ा हम लोग लें

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

लगभग एक हजार जानें नागा—कुकी संघर्ष में जा चुकी थी और पहली बार मणिपुर में साम्प्रदायिक दंगा भी हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यह केवल इस सरकार का शासनकाल था जब मैती और मुस्लिम के बीच साम्प्रदायिक हिंसा भड़की और एक ही दंगे में सौ से ज्यादा जानें ले ली गई। लेकिन आपको याद होगा, उस समय समाचार पत्रों की सुर्खियां इस चीज को छाप रही थी। सितम्बर के मध्य में दो घटनाएं ऐसी घटी थीं, जिसने समूचे देशवासियों के दिलों को दहला दिया। 14 सितम्बर को एक घटना घटी थी, जहां मणिपुर के सेनापति जिले के जौपी गांव में 90 लोगों को घर से बाहर बुलाकर के नागा विद्रोहियों ने गोलियों से भून दिया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद 21 सितम्बर को तमिलांग जिले में तम्मई उपखंड के तालोप गांव के अन्दर जो कुकियों का गांव था, रात के समय 13 बच्चों को जिन्दा जला दिया गया था। 14 लोग भी उनके साथ जलाए गए थे। वह गांव केवल 35 घरों का गांव था। वहां आग लगा दी गई थी और 13 बच्चे जिन्दा जला दिए गए थे। यह वह दिन था जिस दिन हम लोगों ने मांग की थी कि आज संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, सरकार नाम की कोई चीज मणिपुर में रही नहीं है और आज सरकार को चाहिए कि वह धारा 356 जिसको वह हम लोगों के खिलाफ इन्वोक करते रहे हैं,बेवजह तबोक करते रहे हैं, आज उस धारा — 356 को इन्वोक करने का दिन आ गया है और आज चाहिए कि सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। लेकिन दुख है यह बात कहते हुए, उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 28 सितम्बर को स्वयं राज्यपाल यहां मिलने के लिए आए। प्रधान मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और जिस बात की हमने मांग की थी, उन्होंने वह बात जैसी की तैसी कही कि वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आप कृपा करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। 29 तारीख को समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें छपी, जिसमें कहा गया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है। लकिन हम लोग पढ़ने को रहे, उसके बाद अखबार टटोलते रहे, कहीं हमको यह खबर औपचारिक रूप से सुनने को नहीं मिली कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यहां से जब राज्यपाल लौटे, शायद उनको यह आश्वासन दिया गया होगा, वहां जाकर 5 अक्तूबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। वह रिपोर्ट जो सदन के पटल पर कल रखी गई थी। वह रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। 5 अक्तूबर की तारीख इसके ऊपर लिखी गई है। कम से कम उसके बाद तो 24 घंटे की देरी भी नहीं करनी चाहिए थी सरकार को और 5 अक्तूबर की इस रिपोर्ट के बाद तुरन्त मणिपुर के अन्दर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। लेकिन मुझे दुख है यह कहते हुए कि फिर से क्षुद्र राजनीति ने अपना खेल खेला और कुछ सलाहकारों ने सरकार को कहा कि मणिपुर में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, छः प्रदेशों में छः विधान सभाओं के चुनाव होने हैं। अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा तो एक कांग्रेस की सरकार की असफलता के आरोप उनके ऊपर एक आरोप लगेगा। पूरे देश में यह बात जाएगी कि जहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी यह तमाम की तमाम चीजें बाहर आएंगी, इसलिए आप अभी राष्ट्रपति शासन मत लगाइए। मुझे दुख है कि जो बात 22 सितम्बर को हो जानी चाहिए थी, जो बात 6 अक्तूबर को हो जानी चाहिए उसके लिए दो महीने का समय लिया गया और 31 दिसम्बर की रात को केवल नए साल के आने के कुछ घंटा पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि क्षुद्र राजनीति का खेल खेलकर के जिस तरह के मणिपुर में राजनीतिक हालात इन्होंने बनाए हैं उसी तरह इस राष्ट्रपति शासन के देरी से लगाने में भी इन्होंने उसे राजनीति का खेल खेला है।

महोदय, इस सरकार के आने के बाद यानी फरवरी, 1990 में मणिपुर में जो चुनाव हुए, उसके बाद दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं। फरवरी 1990 में चुनाव हुए थे और राजकुमार रणबीर सिंह की सरकार वहां पर आई थी लेकिन उसके बाद विधायकों का दल-बदल हुआ और उसके कारण फरवरी 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फरवरी 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सरकार भंग कर दी गई लेकिन विधानसभा नहीं तोड़ी गई। हमारी 4 सरकारें जिस समय भंग की जाती हैं तो बिला-वजह विधान सभा तोड़ी जाती है। हम कहते हैं कि अगर सरकार के शीर्षस्थ मुख्यमंत्री के बारे में आपको किसी तरह का ऐतराज है कि उन्होंने कारसेवकों का साथ दिया है, उनके गले में मालाएं पहनाई हैं तो भी आप कम से कम विधान सभाओं को बरकरार रख सकते हैं लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें तोड़ी जाती हैं तो ये सरकार साथ में विधान सभाओं को भंग करती है, नए चुनावों का ऐलान करती है लेकिन जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें तोड़ी जाती हैं या जहां कांग्रेस की सरकार के आने की

संभावना दिखाई देती है, वहां यह सरकार केवल उस सरकार को भंग करती है, विधान सभा को नहीं तोड़ती है और फिर विधायकों की खरीद-फरोक्त करके अपनी सरकार बनाती है।

महोदय, यहां मणिपुर में फरवरी 1990 में जो सरकार आई थी, वह कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आर०के० रणबीर सिंह की सरकार थी, एक सांझा सरकार थी लेकिन खुद अपनी ओर से विधायकों से दल-बदल करवाकर इन्होंने वहां दोबारा से सरकार बनाई आर०के० दोरेन्द्र सिंह की ओर दोरेन्द्र सिंह की सरकार अप्रैल 1992 में आई। फरवरी 1992 से अप्रैल 1992 तक राष्ट्रपति शासन लगा और 8 अप्रैल, 1992 को दोरेन्द्र सिंह की सरकार सामने आई, लेकिन 31 दिसम्बर को उस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और दोबारा फिर विधान सभा बरखास्त नहीं की गई। इस समय विधान सभा बरखास्त नहीं है असेंबली इनिमेटेड सस्पेंशन में है। खरीद-फरोख्त का सिलसिला जारी है और यह कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह से खरीद-फरोक्त करके दोबारा से मणिपुर के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके।

अभी मंत्री जी जिक्र कर रहे थे गवर्नर साहब की रिपोर्ट का और कह रहे थे कि ये-ये कारण हैं जिनकी वजह से हमको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मुझे खुशी होती अगर वह गवर्नर की रिपोर्ट का वह हिस्सा भी पढ़ते जिससे पता चलता कि ये कारण पैदा क्यों हुए। मैं आपसे बड़े अदब से यह कहना चाहूंगी कि जब तक हम इन कारणों में नहीं जाएंगे, तब तक हम मणिपुर या पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। वहां केवल कांग्रेस के नेतृत्व में 6 दलों की सांझा सरकार नहीं चल रही थी बल्कि कांग्रेस स्वयं वहां बहुगुटीय पार्टी के रूप में काम कर रही थी। यह बात मैं नहीं कह रही हूं, यह बात सदन के पटल पर रखी गई गवर्नर की रिपोर्ट कह रही है। अगर आप कहें तो मैं वह हिस्सा पढ़कर सुना सकती हूं जहां गवर्नर कह रहे हैं कि 26 विधायकों का कांग्रेस का दल वहां 3 गुटों में विभाजित है। उनके नाम लिए हैं गवर्नर साहब ने। उन्होंने कहा है—

> "Within the Congress combine of 26 MLAs consisting of Congress (I) 13, Manipur Congress 7 and unattached 6, there are three factions under S/Shri R.K. Dorendra Singh, Rishang Keishing and R.K. Jaichandra Singh."

ये तीनों के तीनों कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस वहां बहुगुटीय पार्टी के तौर पर काम कर रही है और इसके आगे जो बात कही है उससे तो मेरा माथा शर्म से झुकता है कि अपने स्वार्थ साधने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सरकार में रहने वाले मंत्री और वहां कांग्रेस के सर्वमान्य नेता कहे जाने वाले लोग आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को संरक्षण दे रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रही हूं, इस सदन के पटल पर रखी गई गवर्नर की रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया है मैंने तो अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात को लिखा था, मैंने तो अपनी जानकारी के आधार पर कहना ही था लेकिन जब कल गवर्नर की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई और मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो देखा कि राज्यपाल महोदय स्वयं कन्फर्म कर रहे हैं उस बात को। मैं रिपोर्ट का वह हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहूंगी—

> "Shri Rishang Keishing is in open revolt against the Chief Minister and in the very first meeting with me on September 1, 1993 presented me with a proposal to form an alternative Ministry with him as the leader. The Chief Minister has not only failed to discipline him, but by his inaction left the field free for Shri Rishang to carry out his evil designs of aiding and abetting the NSCN(I) and subvert the Government machinery and Police."

आपको मालूम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड जो नागा विद्रोहियों का सबसे प्रमुख विद्रोही संगठन है, उसको समर्थन देने का आरोप स्वयं राज्यपाल ने लगाया है। वह आगे कहते है— "Shri Rishang has also precipitated the Naga-Kuki conflict and gave it the colour of an ethnic conflict."

आगे देखिए— "The Chief Minister himself is suspected of aiding a faction of the Meitei extremists (ME) and he is definitely supporting Shri C. Doungel, Finance Minister from Congress (S) and a Kuki, to counter Shri rishang and thereby providing tacit support to the Kukis."

यानी एक ग्रुप नागा विद्रोहियों को संरक्षण दे रहा है और मुख्य मंत्री स्वंय मैती और कुकी-ग्रुपों को संरक्षण दे रहे हैं और गृह मंत्री जब यहां रिपोर्ट पढ़ते है तो कहते है कि नागा विद्रोहियों और कुकियों में सशस्त्र विद्रोह हो

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

रहा था इसलिए हमेंराष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। यह नागा और कुकियों का सशस्त्र विद्रोह कौन करवा रहा था। अच्छा होता वे रिपोर्ट का यह हिस्सा भी पढ़ देते ताकि आपको पता चलता कि क्या कारण है। जब तक आप इन कारणों में नहीं जाएंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। वहां राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखना सबसे बड़ा कारण है। वहां का राजनीतिक नेतृत्व धरती से कटा हुआ है। वह संरक्षण देता है बागी संगठनों को यह अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए उनको संरक्षण देता है। इसलिए नागा सशस्त्र विद्रोहियों और कुकियों में विद्रोह रात दिन होता है और 13-13 बच्चे जला दिए जाते हैं और 90-90 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। इसकी परवाह नहीं है कांग्रेस को। केवल यही सोचा जाता है कि अपनी ताकत को कैसे बढ़ाए। अपने ग्रुप को ऊपर करके दूसरे ग्रुप को किस तरह से नीचे गिराएं, यह काम कांग्रेस पार्टी कर रही है।

दूसरा कारण यह है कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बिलकुल ध्वस्त हो गई है। उपसभाध्यक्ष जी, जब सांझी सरकारें चलती हैं तो उनकी दबावों के चलते प्रशासन पर पूरी तरह पकड़ नहीं होती। लेकिन मणिपुर में तो बिल्कुल ही पकड़ नहीं है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मणिपुर और त्रिपुरा कैडर के जितने आफिसर हैं उनमें से कितने मणिपुर के अंदर पोस्टेड है। मेरी अपनी जानकारी यह है कि मणिपुर के बाहर अधिकतर लोग पोस्टेड हैं, इक्का दुक्का अफसर मणिपुर के अंदर लगे हुए हैं। कभी इसके कारणों की आपने खोज की है कि क्यों मणिपुर में इस कैडर के अफसर नहीं रह पाते। क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार बुरी तरह से व्याप्त है? वहां की सरकार भी नहीं चाहती थी कि गैर-मणिपुरी अफसर वहां रहे। वहां के अफसर अपनी जेबों में पैसा बटोरने का काम करते हैं।

इसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा कारण है कि मणिपुर और दूसरे प्रदेशों के अंदर जो पैसा दिया जाता है उसे विकास में नहीं लगाया जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरी नार्थ ईस्ट के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है। लेकिन उसके पास अधिकार क्या है क्या उस डेवलपमेंट काउंसिल को जो पैसा दिया जाता है उसकी आपने आज तक मॉनिटरिंग की है? आप पैसा फ्लड कर रहे हैं वहां पर, वहां पैसे की बाढ़ लगा दी है आपने पूर्वोत्तर के अंदर लेकिन वह पैसा चंद राजनेताओं और नोकरशाहों की जेबों में चला जाता है। वह पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया जाता। इसलिए इनसरजेंसी वहां पर पनपी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप उस पैसे की मानिटरिंग करेंगे, उस पैसे की निगरानी करेंगे तो इनसरजेंसी की समस्या का निदान कर सकते हैं— अन्यथा नहीं।

श्रीमन, इसमें हमारे पड़ोसी देशों की भी भूमिका है। मुझे दुख है यह बात कहते हुए कि कुछ दिन पहले आर्मी की एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसका प्रिसिडेंट नहीं हैं। आमतौर पर यह परंपरा नहीं है कि आर्मी प्रेस रिलीज़ जारी करके अपनी बात कहे। लेकिन पहली बार आर्मी हेडक्वार्टरस से पी०आई०बी० ने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि पूर्वोत्तर में आइ०एस०आइ० और 15 फंडामेंटेलिस्ट आर्गनाइजेशन काम कर रही है और यहां से गृह मंत्री गए थे, राज्य गृह मंत्री गए थे। गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों ने अपने बयानों के अंदर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि नार्थ ईस्ट के अंदर आइ०एस०आइ० का प्रैजेंस है।

आर्मी ने जो रिलीज दी उसमें उन्होंने केवल 15 फंडामेंटेलिस्ट आर्गेनाइजेशन की बात नहीं की बल्कि यह कहा कि वह 15 फंडामेंटेलिस्ट आर्गेनाइजेशंस यहां काम कर रही हैं जिनको पाकिस्तान और बंगलादेश की शह मिली हुई है, कहा कि विद द ल्पैकिंग आफ पाकिस्तान एंड बंगलादेश। लेकिन मैं यह कहूंगी कि मणिपुर के संदर्भ में एक और पडोसी देश का नाम यहां जोड़ना पड़ेगा म्यांमार यानी बर्मा। जब मियानमार के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन शुरू हुआ, तो सू की के संदर्भ में या वैसे, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए कभी-कभी भारत को कोसना शुरू किया। मियानमार के प्रेजेन्ट रिजिम के तब से वहां के सैन्य तानाशाह हमारे मणिपुर और नागालैंड के विरोधियों को संरक्षण दे रहे हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। एन एस सी एन के लोगों को चाहे बंगलादेश जाना हो, चाहे बर्मा जाना हो, मणिपुर होकर जाना पड़ता है। उनकी प्रेजेंस वहां एन एस सी एन की प्रेजेंस है, एच.पी.सी. यानि हैमार पीपल कन्वेंशन की प्रेजेंस है। ये सारे के सारे बागी संगठन आज मणिपुर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बंगलादेश और बर्मा की शह लेकर, उनका संरक्षण लेकर एन एस सी एन के लोग प्रवेश करें यह एक बड़ा कारण है। इसको हमें देखना होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा देना केवल इन चीजों का उपाय नहीं है। राष्ट्रपति शासन तो देश में 1950 से लेकर आज तक 99 बार लग चुका है। अकेले मणिपुर में 5 बार लग चुका है। मार्च 73 से 74 तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 79-80 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया जो कुछ देर तक चला। फिर 81 में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन

जो जून 82 तक चला। उसके बाद इस सरकार के आने के बाद, जैसा मैं कह चुकी हूं दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार आपने फरवरी 92 से अप्रैल 92 तक लगाया और 31 दिसम्बर से अब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यह अभी तक चल रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रपति शासन एक तात्कालिक औजार के रूप में....

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): You have already taken about 17 minutes. How many minutes more are you likely to take?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पांच-सात मिनट लूंगी। मैंने पहले ही पूछा था इसके लिए कितना समय रखा गया है....।

THE VICE-CHAIRMAN: You have been allotted 16 minutes which you have already taken. Please try to finish within another three or four minutes.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पांच-सात मिनट में समाप्त कर दूंगी। बिल्कुल टु द प्वाइंट कह कर समाप्त कर दूंगी। मैं आप से कह रही थी राष्ट्रपति शासन एक फौरी उद्देश्य के लिए, एक तात्कालिक औजार के तौर पर उपयोग किया जा सकता है लेकिन वह किसी चीज का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान के लिए हम को वहां की ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ेगा, तात्कालिक समाधान के लिए आप राष्ट्रपति शासन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन स्थायी समाधान के लिए आप को नार्थ-ईस्ट के लोगों के संस्कारों को देखना पड़ेगा, पूर्वोत्तर में मणिपुर और मणिपुर में तो इन्सरजेंसी का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि मणिपुर में नागालैंड से ज्यादा इन्सरजेंसी है। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल डिस्टेंस, एक भावनात्मक दूरी है। आज देश को खबर नहीं है मणिपुर के बारे में और मणिपुर के लोग देश के बारे में नहीं जानते। मैं अदब से कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय को भी फुर्सत नहीं है पूर्वोत्तर जाने की। सामान्य स्थिति में कोई मंत्री पूर्वोत्तर नहीं जाता है। हां, जाते हैं जब चुनाव होता है जब डिफेंस हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। जाते हैं जब विधायकों की खरीद-फरोख्त करनी पड़ती है, जाते हैं जब किसी दूसरे दल की सरकार को गिराना होता है। लेकिन वैसे सामान्य समय में पूर्वोत्तर के लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए, उनकी समास्याओं को जानने और समझने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए किसी मंत्री के पास फुर्सत नहीं है वहां जाने की। मैं कहना चाहती हूं अगर पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो सामान्य समय में जाकर वहां बैठें, देखें और वहां के संस्कारों को समझें और मणिपुर की जमीन में से एक समर्थ नेतृत्व पैदा करें जो समर्थ नेतृत्व वहां की सत्ता को संभाल सके। राष्ट्रपति शासन जैसा उपयोग करके या प्रयोग करके आप वहां की चीजों को संभाल नहीं सकते। आपको अपने पड़ोसी देशों की दृढ़ता से कहना होगा कि वे आपके आन्तरिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप न करें। आपको अपनी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आज आर्मी डिप्लाए की हुई है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आर्मी को फायर फाइटिंग के चार्ज के तौर पर लगाते हैं। जब कोई वारदात घट जाती है तो आर्मी को लगा दिया जाता है लेकिन आर्मी की प्रेजेंस का फायदा उठाकर समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कोई बात नहीं की जाती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन्होंने पूर्वोत्तर की समस्याओं के समाधान के लिए केवल तीन रास्ते अख्तियार किये हुए हैं। पहला यह कि धड़ल्ले से पैसा भेज दो, बेतहाशा पैसा भेज दो। पैसे से काम नहीं बने तो फौज लगा दो। पैसे और फौज दोनों ही अगर नाकामयाब हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन पैसा, फौज और राष्ट्रपति शासन तीनों पूर्वोत्तर की समास्याओं का समाधान नहीं है। पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको अपने अन्दर राजनैतिक इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। मेरी मांग है आपसे, मैंने राष्ट्रपति शासन लागू करने का ज़रूर समर्थन किया है, देर से लगाए जाने का विरोध किया है, आधा-पचद्धा लगाए जाने का भी विरोध किया है लेकिन अब मेरी मांग है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाए जाने की मूर्खता सरकार न करे बल्कि वहां पर चूंकि हार्स ट्रेडिंग चल रही है, विधायकों की खरीद-फरोख्त का सिलसिला जारी है, आम चुनाव में वैसे भी 10 महीने रह गये हैं, फरवरी 1995 तक इस विधान सभा का कार्यकाल है, फरवरी, 1995 के अन्दर हर हालत में चुनाव होने हैं, उससे पहले-पहले आप असेम्बली को डिज़ाल्व करिये और वहां पर नये चुनाव कराइये। चुनाव से पहले वहां पर समर्थ नेतृत्व पैदा करिये जो वहां पर नये चुनाव कराइये। चुनाव से पहले वहां पर समर्थ नेतृत्व पैदा करिये और वहां पर नये चुनाव कराइये। चुनाव से पहले वहां पर समर्थ नेतृत्व पैदा करिये जो वहां सत्ता सम्भालने के लिए कारगर हो सकेगा तब आप वहां की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। एक बात और मैं सदन के नोटिस में लाना चाहूंगी। चुनावों को देखते हुए वहां चुनाव की धांधलियां

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही शुरू हो गई है। मेरे पैर की धरती खिसक गई जब मेरे मणिपुर स्टेट की इकाई ने आकर के मेरे हाथ में एक दस्तावेज़ पकड़ाया और कहा कि वह केवल एक असेम्बली कांस्टीट्युंसी का ब्रेक-अप है। वह असेम्बली कांस्टीटयुंसी नम्बर 35 खामबोक है जहां पर हमारे कार्यकताओं ने जाकर के देखा, जब वोटर्ज़ लिस्ट को देखा तो उनके कान खड़े हुए कि इतने मतदाता कहां से आ गये। फिर उन्होंने सेंसस के रिकार्ड को देखा। सेंसस का रिकार्ड मंगा कर यह पाया कि मतदाता सूची में जो मतदाताओं की संख्या है वह कुल आबादी में भी बहुत ज्यादा है। मैं वह डाकुमेंट लाई हूं और आप कहें तो मैं सदन के पटल पर भी रख सकती हूं। इनमें से अगर मैं केवल तीन आंकड़े बताऊं। यह 2 आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युंसी नम्बर 35 खामबोक असेम्बली कांस्टीट्युंसी का है। इसके तीन गांवों का सर्वे हुआ था। पहला था अथोकपाम यहां की टोटल पापुलेशन इन्कलुडिंग ज़ीरो टू सिक्स ईयर्स अर्थात बिलकुल इनफैंट से ले कर 6 साल तक के बच्चों को जहां जोड़ा गया है, सेंसस जो हुआ उसकी फोटो कापी भी मैं लाई हूं जहां से मैं यह आंकड़े ले रही हूं वह संख्या है 1777 और उसी अथोकपाम के अन्दर जो वोटर्ज़ लिस्ट है उसकी संख्या है 2722। यदि आप कल के पैदा हुए बच्चों को भी मतदान का अधिकार दे दें तो उससे भी एक हज़ार ज्यादा लोग मतदाता सूची में दिखाए गए हैं। जब परसेंटेज निकाली गई तो पापुलेशन इनक्रीज़ है 29 परसेंट और वोटर्ज़ इनक्रीज़ है 102 फीसदी। इसी तरह एक और गांव है ऊयाल जहां इनक्रीज़ इन पापुलेशन है 23 परसेंट और इनक्रीज़ इन वोटर्ज़ है 120 फीसदी। इसी तरह से एक और गांव है संगाइयूरपाम जहां इनक्रीज़ इन पापुलेशन है 39 परसेंट और इनक्रीज़ इन वोटर्ज़ है 63 परसेंट अर्थात् 29 फीसदी, 23 फीसदी और 39 फीसदी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है लेकिन आपकी मतदाता सूची जो बढ़ोतरी दिखाती है वह है 63 फीसदी, 102 फीसदी और 120 फीसदी। हमने जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह दस्तावेज थमाया है, उनको जाकर के हमने कहा कि आप इसकी इन्क्वायरी करवाइये कि आबादी से ज्यादा वोटर्ज़ लिस्ट में संख्या कैसे है। सेशन साहब ने उसी समय इन्क्वायरी मार्क कर दी थी और कहा कि कोई इलेक्टोरल रोल तब तक नहीं छपेगा जब तक यह मेटर उनकी सेटिसफेक्शन के अनुसार रिज़ाल्व नहीं कर ली जाती। (समय की घंटी) आपने दूसरी घंटी बजा दी है इसलिए मैं केवल एक बात अंत में कहना चाहूंगी। आज जो चेतावनियां हम दे रहे हैं उन चेतावनियों को सरकार सुन ले तो बहुत अच्छा है वरना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि मुझे भरोसा है कि आप सुनेंगे नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई चेतावनी देती है तो आप मौन साधे रहते हैं और जब अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोलता है तब आपको उस समस्या के सीरियसनेस का अहसास होता है। यही कश्मीर के मामले में हुआ। हम वर्षों से दुहाई दे रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, पिछले संसद के तीन सत्रों से कह रहे हैं आपसे कि कश्मीर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ लेकिन आप नहीं चेते। मिक्स्ड सिग्नल सरकार देती रही। अब अमरीकी राष्ट्रपति बोले हैं तो अब सरकार गम्भीरता से सोचने लगी है। मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि अब कश्मीर के बाद दूसरा निशाना पूर्वोत्तर होने वाला है और पूर्वोत्तर के सात राज्य होने वाले हैं इसलिए आप समय रहते चेत जाएं। यह मत सोचिये कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, कल बिल क्लिंटन बोलेगा तो हम सीरियस होंगे। अगर आज आप चेत जाएं तो समय रहते चीज़ें काबू में आ जाएंगी वरना बहुत देर हो जाएगी। एक बार अपनी गिरेबां में झांक कर देखें। इस बात का अहसास करें कि क्या कारण है कि इम्फाल की पहाड़ियां जहां बैठकर के अंग्रेज विश्व युद्ध जीत सकता है, उसकी योजना बना सकता है। इम्फाल की वे पहाड़ियां जहां से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पूरे हिन्दुस्तान को झकझोर सकता था आई० एन० ए० का गठन करके आज वह इम्फाल हिंदुस्तान का सिरदर्द क्यों बन गया गया है, आज वह ड्रग ट्राफिकिंग का अड्डा क्यों बन गया है, आज वह स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा क्यों बन गया है। आज वहां राननैतिक अस्थिरता क्यों है। मैं आपसे एक बात का आश्वासन दिलवाना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ करने की जरूरत है। तमाम राजनैतिक दलों को वहां भूमिका निभाने की जरूरत है। अपनी ओर से अपने दल की ओर से इस कार्य में मैं इस पुनीत कार्य में देश को अखंड रखने के कार्य में अपने दल की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देना चाहूंगी आपको और इस आश्वासन के साथ ही आपसे पुनः मांग करना चाहूंगी कि आप भी दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठें। पूर्वोत्तर को बचा लीजिए, मणिपुर को बचा लीजिए और अभी राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके वहां नये चुनाव, ताजा चुनाव करवाकर सत्ता जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपने की तरफ बढ़िए। यही कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत गौर से सम्माननीय

सदस्या श्रीमती स्वराज का भाषण सुन रहा था। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसके लिए उन्होंने अच्छा कहा। लेकिन सम्भाषण करते वक्त जो उन्होंने कुछ बातें कीं...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): वे ज्यादा अच्छी कहीं।

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे:... उनमें अर्ध सत्य था, पूर्ण सत्य नहीं था। उनकी नीति यही रही है कि अर्ध सत्य कहते रहेंगे और पूर्ण सत्य की ओर वे जायेंगे नहीं। इसलिए वे हमेशा घपले में आ जाते हैं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): आप असत्य की ओर ही जाते हैं।

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं बताता हूं। थोड़ा-सा पूर्वोत्तर विभाग को जरा देख लें, चाहे अरूणांचल हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, ये सब हमारे नार्थ ईस्ट एरिया के विभाग हैं। वहां एक तरफ चायना, दूसरी तरफ भूटान, तीसरी तरफ बंगलादेश और चोथी तरफ मायनामार, ये सभी सरहद के प्रांत है। हमने 1960 में देखा कि हमारे अरूणांचल की सरहद पर चायना के साथ क्या हो गया। आज भी बंगला देश के बार्डर पर — अभी-अभी की बात है, 8-10 दिन पहले की बात है कि बंगलादेश के कई लोगों को अपने देश को भेजने का कार्य त्रिपुरा के गवर्नर ने वहां पर किया। यह भी हमारे सोच में आना चाहिए। वैसी ही स्थिति मणिपुर की है।

सम्माननीय सदस्या ने कह दिया कि 1990 में जो सरकार आ गयी थी उस सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो क्यों निकाला गया उनको? हम तो वहां नहीं थे कांग्रेस तो नहीं कह रही थी कि हम वहां कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहां भी वह सरकार नहीं रही।

थोड़-सा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1992-93 में वहां कितने इंसीडेंट्स हो गये। महोदय, वहां 1992 में जो केसेज हो गये उनमें बम एक्सप्लोजन्स 13 हो गये तो 1993 में 36 हुए, 1992 में 22 पुलिस वालों को मारा गया तो 1993 में 41 लोगों को मारा गया, 1992 में 43 सिविलियन लोगों को मारा तो 1993 में 119 को मारा। आर्म्स के कितने इंसीडेंट हुए? 1992 में 12 की तो 1993 में 113 की लूट हो गयी।

भारत सरकार इन प्रांतों को बड़े गौर से देख रही है। नार्थ ईस्ट जो हमारा एरिया है यह पहाड़ी इलाका है। वहां बहुत सभ्य और आनेस्ट लोग हैं। वहां एक तो भारतीय नीति पर थोड़ा-थोड़ा करके अच्छी तरह का रवैया चल रहा है लेकिन बीच के कुछ वक्त में भारत की कई विशिष्ट रूपों की पार्टियां वहां जाने का प्रयास कर रही थीं। थोड़ा-सा सिक्किम की ओर हम देखें। सिक्किम में आज भी गड़बड़ी चली है। तो वहां तो कांग्रेस का कोई काम नहीं चलता है, कांग्रेस का संगठन कोई एग्रसिव नीति लेकर नहीं चलता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मिजोरम की बात में कहना चाहता हूं कि वहां अभी-अभी फ्री एंड फेयर एलेक्शन हो गए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं कि साल भर के पहले वहां जो नीति चल रही थी, आप भी जरा सोचिए भारतीय जनता पार्टी भी, जहां अच्छी तरह से राज चला है वहां जाकर आप कुछ न कुछ करते रहते हैं और यहां आकर कहते हैं कि अबव पोलिटिक्स (above politics) हम पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशिष्ट नीति से देखना चाहते हैं। उनकी भलाई देखना चाहते हैं। आप मेघालय में क्यों गए दशहरे के दिन गड़बड़ी करने के लिए? वहां इतना अच्छा था मेघालय में, लेकिन गए साल दशहरे के पहले वहां की जो एथनिक कम्युनिटी है उनमें वहां संघर्ष कराने का काम किया।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: यह बिल्कुल सत्य नहीं है।....(**व्यवधान**).... वहां तीन सालों से लगातार दुर्गा पूजा के ऊपर आपत्ति हो रही है। इन झगड़ों में हम लोगों की पार्टी का कोई हाथ नहीं है।

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: उपसभाध्यक्ष जी, उसी के कारण वहां के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुनकर दे दिया और कांग्रेस के मुख्य मंत्री जी अभी वहां काम कर रहे हैं। यदि वह ठीक नहीं होता तो नहीं देते। वही हो गया मिजोरम में, वही हो गया नागालैंड में, कांग्रेस के सिवाय कोई है? हम लोग भी आजमाते हैं कि किस तरह की राजनीति आप कहते हैं। आप कह रहे थे अभी कि सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाकर निबटाया। इतना बड़ी जनता ने आपको अधिकार दे दिया था सरकार चलाने के लिए, लेकिन मंदिर में आप इतने रस गए, इतने घुस गए थे, अरे मंदिर तोड़ते वक्त जिस सत्ता में, शासन पर बैठे हो, उस नीति को आपने खत्म कर दिया और बात एडमिनिस्ट्रेशन की कहते हो। आपके चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे कि हमारे पुलिस वाले वहां नहीं जायेंगे, मंदिर तोड़ने दो। सत्ता लोगों ने दी, लेकिन सत्ता चलाने को जिस सरकार को, पक्ष को नहीं आता है तो क्या उपयोग है उस पक्ष का? ....(**व्यवधान**)....

श्री महेश्वर सिंह हिमाचल प्रदेश: हिमालय वालों ने क्या किया था?

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: आप सुनिए, इतना बड़ा सरकार चलाने का अधिकार दिया था। एक हिम्मत लगती है जो कांग्रेस वालों के पास है, सरकार चलाने के लिए जो बुद्धि लगती है वह कांग्रेस के पास है। आपको उपलब्धि दी लेकिन चलाने की ताकत ही नहीं है। एक्टिविस्ट विचार लेकर चलते हैं "हिन्दुत्व की जय हो"। इस देश में दूसरे भी कई लोग रहते हैं। इस देश में मुसलमान रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, दलित रहे हैं, इसका कोई विचार नहीं है। एक विचार, दूसरा कोई नहीं है। अभी थोड़ा सा सोचने की बात है। मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में आपका राज जाने के बाद थोड़ा तो आप आत्म चिंतन करने का काम करें। गरीबों की नीति नहीं अपनाते हो। इस देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीति है उससे राज नहीं चला पाते हैं तो क्या आपको सबक और शिक्षा मिलती है, क्या सजा मिलती है लोगों से? यह आपने अपनाया है तो अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास मत करें। मणिपुर में इलैक्शन आने वाला है। अभी आप कह रहे हैं, लेकिन छोड़ दें वहां आपने प्रयास किया। 24 सीटें कहां लगाई नागालैंड में एक भी सीट नहीं आ गई। एक तो आ गया विधायक मेघालय में लगाए 18 लोग, एक तो विधायक आ गया? इससे थोड़ा सा सबक सीख लें कि उस रास्ते में अभी हमें जाना नहीं। जो राज कर रहे हैं अच्छी तरह से वहां के लोगों को सुविधा दें। मैं यह मानता हूं और सम्मानीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह भी हमारा दर्द है कि जितना पैसा भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को दे रही है वह ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है। इससे मैं सहमत हूं। इसके लिए आपको में यह बताना चाहता हूं उपसभाध्यक्ष जी, कि जब हमने देखा, वहां मेरा भी कुछ हिस्सा है मेरी पार्टी की ओर से मैं कुछ राज्यों को देखता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री संघप्रिय गौतम: पैसा का हिस्सा है?

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं बोलता हूं, मैं पार्टी की ओर से इंचार्ज बनकर देखता हूं। यह हमारे जब ख्याल में आ गया कि प्लानिंग और फाइनांसेज में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी है महाराष्ट्र में जो वहां के कैडर के मेघालय के कैडर के जो अधिकारी थे, सेक्रेटरी लैवल के जो अधिकारी थे, हमने उनका काम देखा था, जिन्होंने फाइनांसेज में काम किया, जिन्होंने प्लानिंग का काम किया है महाराष्ट्र में एक विशिष्ट लैवल का प्लानिंग है और लोगों को सुविधा दे दी है। तो इसके लिए महाराष्ट्र के उस अधिकारी को हमने अभी एन०एस०सी०ए० North East Coordinate Council में लगाया है और वहां बैठकर उन्होंने उस काउंसिल में एक विशिष्ट डिसीप्लीन लाने का काम किया है यह भी सरकार ने किया है। प्रधान मंत्री जी ने गौर से इस काम को देखा है और मैं आपको मालूमात देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, एक-दो महीने पहले मेघालय में मंत्रिमण्डल की एक बैठक हुई जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने भाग लिया। उस में उन्होंने वहां का जो निग्लेक्टेड एरिया है उसमें किस तरह डवलपमेंट वर्क किया जाए, इस पर उन्होंने विचार किया। आप थोड़ा सा देखिए, आज ही सदन में प्रधान मंत्री जी ने डा० सिलवेरा का मंत्री के रूप में इंट्रोडक्शन कराया। अभी तक वहां से किसी को प्रधानता नहीं दी गयी, लेकिन नरसिंह राव जी ने मिजोरम का एक मंत्री बनाया। उन्होंने एक अपार्चुनिटी दे दी है कि आप अपने प्रांत का और अपने विभागों का काम अच्छी तरह से करिए ....(व्यवधान).... वह एक पहाड़ी इलाका है और उनको डिपार्टमेंट भी इस तरह का दिया है जिसमें कि पब्लिक हैल्थ वहां जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है। तो इन कामों के लिए उन्होंने अच्छी तरह से प्रबंध किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि हम वहां कांग्रेस की सरकार चलाना ही चाहते तो क्या सस्पेंडेड एनिमिशन करते? कांग्रेस को क्या हो गया था कि वह अपनी सरकार खत्म कर दे? लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ गयी तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपनी पक्ष की फिक्र नहीं की, अपने पक्ष का भी विचार नहीं किया। वहां जनता के लिए कुछ दुखद घटनाएं हुई तो उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां की सरकार को बरखास्त किया। यह सब जो एरियाज है उनमें एक नयी थिंकिंग है। जो लोग हैं, यहां के जो सदस्य हैं उनको यह विचार करने की आपर्चुनिटी देनी चाहिए कि अलग-अलग विचार और अलग-अलग वाद की बातें जब चलती हैं तो एक तरह से जहां इनसर्जेन्सी है और देश को तोड़ने की बातें चलती हैं, तो क्या आप यह बातें करोगे या देश को बचाने का काम करोगे? जो छोटे-छोटे पूर्वोत्तर राज्य हैं, अगर वहां कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें राष्ट्र की धारा में लाने के लिए एक नया डायरेक्शन देने की जरूरत है। यदि हम इन बातों पर नहीं सोचेंगे तो हम जो अखण्ड हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं रह सकता है। उसमें तो उसी वक्त कुछ दम रह सकता है जब भारत के छोटे-छोटे भागों से जो लोग इस देश के एकीकरण के लिए आए हैं और संपूर्ण भारत की एक संघीय विचारधारा को लेकर एक विशिष्ट रूप में भारत की विचार प्रणाली में, भारत की जीवन प्रणाली में इकट्ठा

होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी समझाने का काम हमें करना चाहिए कि वहां एथनिक झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसलिए जब "सर्व-धर्म समभाव" की बात हम करते हैं और देश की एक प्रवाह में लाने की बात करते हैं तो वहां इस वक्त आप जैसे जो लोग हैं उनको वहां लोगों को यह समझाना चाहिए कि, नहीं आप भारत की इस भूमि के मालिक हो। आपको उसे तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि इकट्ठा करने का काम करना चाहिए और यह इनसर्जेन्सी का काम और यह आर्म्स और ड्रग्स का हमारी सीमा के अंदर आने का काम होता है, उसको रोकना है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकार का ही काम नहीं है बल्कि एक विशिष्ट रूप से विचार कर के लोगों को रोकना होगा। तभी भारत की जो सीमाएं हैं और उन पर जिस तरह का आज काम हो रहा है, उसे रोकने के लिए हम सब को साथ मिलकर सभी पार्टीज को मिलकर प्रयास करना होगा। इसलिए मैं गृह मंत्रालय और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि सरकार किस पार्टी की है, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को देखते हुए जहां-कहीं गलतियां होती हैं तो उन्हें करेक्ट करने के लिए सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं, मैं उसका उसके लिए अभिनंदन करता हूं। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ, मैं यह कहूंगा कि इन लोगों की एकता के बारे में स्पष्ट रूप से जो कहीं भूमिका है, यह लोगों को अपनाने की, समझाने का काम सरकार करें। यहां उनको अच्छी सुविधा भी मिलें। मुझे खुशी है कि कुछ दिन पहले कई युनिवर्सिटी आई, पूर्वोत्तर विभाग में शिक्षा के लिए उनको दे दी। मेडिकल कालेज दे दिया। जो नई सुविधा जरूरी है, एक तो वहां जाने के लिए कोई यातायात की सुविधा नहीं है। यह सब सुविधा देने का काम है, जिससे संपर्क हो सके पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छी तरह का। यह भी काम सरकार को करना होगा।

आगे, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी भूमिका निभाने का काम किया है पूर्वोत्तर विभाग के लिए ....(व्यवधान)...

श्री संघप्रिय गौतम: बहुत सराहनीय है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: आप आत्मचिंतन करें भारतमाता को साथ रखते हुए, उनको सामने रखते हुए, आप असलियत से आत्म-चिंतन करें, कि यह छोटे छोटे राज्यों में, जहां एकता की बातें हो रही हैं वहां अलगाववाद की भावना डालने की भूमिका आपको नहीं निभानी है और तभी मैं समझूंगा की आप अपना रहे हैं आप यहां बात तो करते हो भारतमाता की नीति की और वहां जाकर बात करते हो अलग बात! ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इण्टरोस्पेकशन की बहुत जरूरत है। चार जगह आपको एक लेसन मिला है। उत्तर परदेश में जो आपने किया, इसकी बहुत बड़ी सजा आपको मिला है। हम तो नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि आप और राज करें। हमने हमारे प्राइममिनिस्टर को हमारी पार्टी बार बार कह रही थी कि यह बहुत कर रहे हैं, आर०एस०एस० के लोगों को वहां भेज रहे हैं, वहां बहुत हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन प्रधान मंत्री बार बार कहते थे कि किसी एक चुनी हुई सरकार को हम हटाना नहीं चाहते। यह नीति थी हमारी, लेकिन आपने सामने खड़े रहकर कहा कि हमारे पुलिस वाले मस्जिद तोड़ते वक्त भी वहां नहीं जाएंगे, नहीं रुकवाएंगे। तो यह कैसे चल सकता है? .....(व्यवधान)..... हां, मस्जिद की बात। अरे, मस्जिद को ही मैं मंदिर इसलिए कह रहा हूं कि उनको वही प्यार है। वही भगवान है वहां भी। अरे, भगवान तो जहां देखो वहां है। सुमन चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, लेकिन आपके पास सुमन नहीं है कागज के फूल हैं खाली। तो कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। आप जरा समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे है आप मेरे साथी, लेकिन बहुत गलत पक्ष में आप जाकर बैठे हैं। जरा इस पक्ष में आइए, जो कर्वधर्म समभाव की बातें करता है और छोटे छोटे राज्यों को .....(व्यवधान).....

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश): यह कागज की नाव भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। .....(व्यवधान) .....

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: सारंग जी, आप मध्यप्रदेश से आए हैं। मैं समझता था कि उस कालीदास की भूमि के सुपुत्र हैं आप, लेकिन उसकी भी नीति आप समझ नहीं पाते हो तो मैं क्या करूं। (व्यवधान) अफजल जी, जरा उनको समझाने का काम कीजिए। बड़े नजदीक रहते हैं आपके। व्यवधान)

महोदय जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सस्पेण्डेड एनीमेशन जो किया है, वह मैं समझता हूं पूर्वोत्तर विभाग के लिए वहां उनके इलेक्शन पर खर्चा भी ज्यादा करना ठीक नहीं है। किसी का राज आए, हम यह नहीं कहेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर निकाला गया है राष्ट्रपति शासन में। कल कोई भी आ सकता है। हम कोई थोड़े ही बंधन डालना चाहते है। हम तो दिल से यह चाहते हैं कि वहां अच्छा डवलपमेंट हो, लोगों को

[श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे]

सुविधा मिलें और वहां की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में रहे क्योंकि यह छोटे-छोटे प्रांत जरूर हैं, परन्तु वहां से बहुत जोर से स्मगलिंग होती है, इसे रोकने का काम भी हमारे होम मिनिस्टर साहब को करना होगा यहां, यह जो स्ट्रेटिजिक्स पाइंट हैं। बम्बई में जो इतना बड़ा कांड हो गया, बम-विस्फोट हो गए, आज भी कुछ न कुछ वहां से चले जा रहे हैं। इसलिए इन सीमाओं पर हमें कंट्रोल करना होगा। इसके लिए वहां अच्छी नीति जरूरी है, स्ट्रोंग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है और अच्छे डवलपमेंट के लिए जब सरकार काम करती है तो मैं मेरे पक्ष की ओर से बोलूंगा कि एक अच्छी नीति वहां आ रही है आज नागालैण्ड से लेकर हमारे मिजोरम तक, मिजोरम से लेकर मेघालय तक और अरुणाचल तक।

उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं यही भूमिका रखना चाहता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं कि एक अच्छा काम सरकार ने किया है और मुझे पूरी आशा है कि हमारे मंत्री महोदय पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आज वहां क्या स्थिति है? राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां क्या स्थिति है? हमारी क्या स्थिति है? क्या आज भी उस तरह लूटिंग वहां हो रही है, आज भी उस तरह की किलिंग वहां हो रही है? यह भी हमें सरकार बताए, यही मैं प्रार्थना उनसे करता हूं।

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to say something about Manipur. Please do not misunderstand me when I stand up to welcome and support the proclamation of President's Rule in Manipur. As a democrat, I feel President's Rule is not liked in principle. But, particularly, in the case of Manipur, we feel that the proclamation was very much delayed. Sir, as early as on 4th of May, 1993, in this very august House, I pleaded for the proclamation of President's Rule in Manipur. And after seven months, it was proclaimed. During those seven months, some 550 precious lives were lost. And these precious lives could have been saved. You might think that 550 lives are not many. But, for a small and tiny State like Manipur, 550 lives are many. In the case of Punjab and Kashmir, 550 lives may not be considerable, but in the case of Manipur, it is a huge number. And those precious lives have been wasted. Our Central Government refused to intervene at that time when that communal-like situation and the mass killings took place in May. Anyway, it is better late than never. On 31st December, 1993, the President's Rule was proclaimed, and we were very glad. In the past one month and 23 days---today is the 22nd Febru-ary— the adminsitration under the President's Rule, under the Governor Lt.-Genl. V.K. Nayar who is a retired Army gentleman and who was in the Eastern Command, has been able to reduce the killings by 20 per cent. But still the killings are continuing.

Sir, now my complaint is that there is a threat to impose, to foist a pure Congress (I) Government by indulging in defections over there. This is my complaint. Sir, about a week back, the North-Eastern Congress (I) Coordination Committee held its meeting in the capital Delhi. The Chief Ministers of the North-East States and the state Congress (i) Presidents of the North-East states were there. There was a very serious discussion there that a pure Congress (I) Government may be foisted over there in Manipur. The news appeared in the local press of Manipur. And the common people there started feeling terrorised. The common people are terrorised that if the Congress (I) Government is again foisted, a reign of terror would come up again. That is the feeling the common people of Manipur are having. So, I would request the Central Government: Let us rise a little above party politics. Our elections are due in January, 1995. That is after 10 or 11 months. There is an attempt to see that immediately before the elections are held in Manipur, a Congress (I) Government is there in order to commit regging, in order to misuse the administrative machinery for winning the elections. Such a partisan approach should be avoided. I would urge the Home Ministry, through you, Sir, that such a partisan approach, such a party consideration should be avoided,

particularly in the case of Manipur and in the North-East.

Sir, our hon. Member Sushmaji has pointed out about the presence of the ISI.

No, only in Manipur but in Assam, in Nagaland, in Mizoram and other North-Eastern regions, the ISI is very active. It is active in Bangladesh which is not supposed to be a hostile country, of course, but the ISI is very active in that country as also in Burma. So, through Myanmar and Bangladesh, ISI arranges infiltration of the underground elements belonging to ULFA or Bodo security force of NSCN or PLA or UNLF and Kuki National Force. All these underground elements have very close contact with the ISI and they get training in Bangladesh bordering Manipur and Mizoram. They get guerilla training. All these insurgents get this training also in some parts of Burma. They not only get training but weapons also. The Governor in his report has said about 200 sophisticated weapons having come from outside India. Of these 200 sophisticated weapons, I believe hardly 10 or 20 weapons might have come about ten years back from our northern borders, say, China. But the rest of the sophisticated weapons are coming through Bangladesh. I would like to know whether our Central Government intelligence department, RAW or other intelligence agencies can take some counter measures to defeat the designs of the ISI in the Noth East. Let me remind the Government of the possible links of the ISI with the CIA. From Mr. Bill Clinton's letter to Gulam Nabi Fei, the so-called Washington based Kashmiri American council it is very clear that the ISI of Pakistan is getting guidance from the CIA. May be, the Government of India, the Home Ministry knows better about it. But I may give a note of warning in this House that the CIA and the ISI are having links in the North-Eastern region of the country. Therefore, while we welcome the imposition of President's Rule, this should not be used to foist Congress-I Government there hastily which would defeat the whole purpose, because disintegration of the North-East would not be the intention of the Government even if it intends to foist a Congress-I Government there.

The Governor in his report on the 5th of October, 1993, has mentioned about infiltration of insurgents in the political parties. There might have been an infiltration in other political parties but infiltration in the Congress Party is very considerable. R.K. Dorendra Singh's leadership has failed; Rishang Keishing, the Deputy Chief Minister has been named as having links with NSCN. Now, if the Chief Minister has links with the insurgents, if the Deputy Chief Minister has links with insurgents, if the Finance Minister has links with insurgents and if the Tribal Development Minister has links with insurgents, then anybody not having links with insurgents, in the Congress Party, would be allowed to lead the Government in the name of Congress-I Party, without looking to the interests of the North East, without looking to the interests of Manipur and that I think would be the most unfortunate and sad situation for the country. Keeping the Manipur Legislative assembly in animated suspension is a threat to the integrity of the North East. The trade and commerce and business have come to a stand still. Business has come to a standstill. The non-local businessmen have fled Manipur because of abduction and extortion. When they approach the Chief Minister saying that such and such insurgent group had demanded Rs. 5 lakhs, what does the Chief Minister tell them? He says: You also give something. I have been paying to them; you also pay something. I am not speaking of any particular Chief Minister.

What is the character of the present Manipur Legislative Assembly? The statistics are revealing. There are 60 Members in the Manipur Legislative

[Shri W. Kulabidhu Singh]

Assembly. Of these 60 MLAs., some three Members, hon. MLAs., have crossed the floor four in past three years. Some other Members have crossed the floor three times. Many have crossed the floor two times in the past three years. Many have crossed the floor two times. Crossing the floor one time is very common among most of the Members. In this set-up of the Assembly, if a Congress (I) -led Government, if a Congress-I-led Ministry, is foisted on the state for two months or one month immediately before the elections, that would be very unfortunate for the country. That would be extremely undemocratic.

Therefore, I demand immediate dissolution of the suspended Assembly. If you try to form a Government with another leader heading the Congress (I) Party, that would be very hazardous. That would be very dangerous for the people of Manipur. In that case, Manipur would go to hell. There would be no business, trade and commerce. There would be no developmental activity at all. Though I am speaking from the Opposition benches, I welcome the imposition of President's rule in the State on 31st December last. Before concluding, I would like to sound one note of caution. Lt. Gen. B.K. Nayar is the Governor there. We told him that he should see that no excesses by the Army take place. This was our request to him. The Governor gave us a very patient hearing. We welcome President's rule. At the same time, on their part, the Central Government should ensure that in future, there are no Army excesses on the people in the name of combing operations. The women organisations are very restive. They are worried whether any Army excesses or atrocities would take place. Up till now, not much has been there. But it should be ensured that these excesses do not take place in future. I, therefore, request the Government, through you, Sir, that the President's rule should continue for some more months and let there be no Army excesses in the name of combing operations. Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Statutory Resolution seeking the approval of the House in regard to the imposition of President's rule in Manipur.

I support the Resolution moved by the hon. Minister of State for Home Affairs. I was hearing the hon. Member fromt hat State. He referred to the situation prevailing in Manipur earlier and, thereafter, during the period of the coalition Government. This is the first occasion wherein all the political parties in Manipur have supported the imposition of President's rule, the reason being, the insurgency situation in the state became so acute and all the political parties, including the Congress (I) party, felt that imposition of President's rule was the only solution to bring the state back to normalcy.

We have been hearing the criticism from the opposition parties, both inside the House as well as outside, that the Congress (I) Government at the Centre was picking and choosing opposition-rule states for imposing President's rule. But here is an example where even though there was a Congress (I) Government, as the law and order situation worsened there, the Congress (I) Government at the Centre, without any partiality, imposed President's rule in Manipur.

Sir, the North-Eastern States are sensitive States.

4.00 P.M.

Insurgency is there. Militant activities are perpetrated by adjoining countries, like Myanmar, Bangladesh, on the other side of the border areas. These militant outfits go there, acquire weapons and come back and indulge in terrorist activites so that they can control that part of the territory for the purpose of economic support.

How did the trouble start? Apart from other things, 11 MLAs belong to NSCN and some of the MLAs are supporting the Kuki groups. That being the case,

running of the administration without any support of the insurgents or militant outfits was not possible. I entirely agree with the hon. Member, irrespective of the party considerations, that not only the Congress (I) but also the Janata Dal and other political parties have links with the militant outfits. Everybody has to accept this fact. The situation was that the NSCN tried to have control over the area, called Moreb, coming on the National Highway No. 39. They wanted to impose Loyalty tax on Kukis which the Kukis opposed. The Kukis claimed that they were the persons who occupied that area, but the Nagas said that they have been there for a long time and the area had been occupied by Kukis by force. This is the tussle between the two groups in the entire State. Even one group goes on to say that they want wider Nagaland. Even the MLAs print on their letter pads 'The Republic of Nagaland', whereas the Kukis claim that it is their land. Therefore, the Chief Minister could not do anything. the Central assistance could not reach the State. The situation could not improve even by sending armed forces. So, the Centre was forced to impose President's rule in that State.

Whatever be the situation, now we have to see that the situation like Jammu and Kashmir does not spread to the North-Eastern States. This is what I would like to tell the Home Minister because whenever we have visited that area, we are told that they have been neglected by the Central Government. They openly express this view to us and to all other political leaders who go there. They complain that the Central Ministers are not visiting, the officials are not visiting, their problems are not being looked into, their problems are not being solved. They feel that they are being alienated. That kind of impression has to be removed from the minds of the people of the North-Eastern States. These are the border States where terrorism is being aided and abetted by the adjoining countries. Manipur is the best example where terrorism is being inflicted by the outside forces and this is possible because the people there feel that they have been alienated. The people there have a feeling that they have been isolated by the Government of India. The burning problem in the North-Eastern States is that of unemployment. The welfare schemes, the welfare measures are not reaching the people. There is no mechanism by which the state Government is able to control the administration. Therefore, the Central Government has to be vigilant in the North Eastern States. You have got several Councils there. You have to monitor the money that you have been sending for the purpose of developmental activities. The children of the North-Eastern States are well-educated. The Christian missions are providing them education. Now they require employment. In the absence of employment opportunities, they are lured by militant outfits. Therefore, the hon. Minister has to concentrate on creating employment opportunities in the State of Manipur so that terrorism can be contained there.

They can talk to the militant groups. What are their demand? Their demands are very simple. They claim that their separate identity should be maintained. That is what they want. Specifically, the Kuki people say that the areas which they are occupying—scattered areas—should be earmarked and there should not be interference in their living by the other group. The other group claims that the Kukis should not enter their area. This is the main problem. Why are they claiming so? There is a reason behind it. There is a sinister design on the part of these two groups. In the Manipur area, which is used for smuggling, if one groups comes there, the income of the other group is affected. Therefore, in the border areas, especially in Manipur, Nagaland and Sikkim, I find that it is a free-for-all. The people who are living in these areas go the Myanmar and Bangladesh freely. There is no security force operating in that area. That is one of the reasons why

[Shri V. Narayanasamy]

people there feel that they can go to any place and get any weapon.

Now, what kind of weapons is your police having there? Weapons which were purchased in the 80's are with them while the militants are having AK-47 and AK-56 rifles. The police cannot cope with the firing range of the weapons which are possessed by the militants. You have to fully arm your police and paramilitary forces there with modern weapons. There is a scheme of the Home Ministry to give to the North-Eastern States, especially for the police and armed forces, bullet-proof vests. Yes, it is good; that will definitely give a kind of protection to the armed forces and the police when they fight the militants. But you have to implement it very effectively.

Sir, I find that the decision taken by the Government in bringing Manipur under President's Rule is perfectly valid. As some hon. Members have said, after one month and 23 days of imposition of President's Rule there, what steps has the Government of India taken in the case of development in the State and in the case of employment in the State? The hon. Home Minister visited the North-East. He had a meeting on January 22 with the Chief Ministers of the North-Eastern States. the Chief Ministers apprised the Home Minister of their problems, especially in the State of Manipur which is dominated by Hindus. I visited that palce and I felt as if I was in South India. I am from South India and I did not feel that I was in a hilly area., The people, their culture, their behaviour, their way of life, are like in South India. I was very happy when I found it so.

The problems of the people of Manipur are not only political. They are social, cultural and, beyond that, those people want to keep their identity. Therefore, it is a very complicated issue. The people of Manipur want to live in peace without interference by the militant groups. To curb the militant groups, the Home Ministry has to take very strong measures. It is only after the State is brought to normalcy that a popular Government can be installed there. I think, it may take at least one year. We want the hon. Home Minister to have a free hand in that State and see that militancy there is controlled, the State is brought back to normalcy, development activities take place, employment potential is created and, beyond all that, the feeling in the people that they form part of India is created in their minds. Unless that impression is created by the Home Ministry, it is a very difficult task for them. I know that the Home Minister is capable of doing it, and I want the hon. Minister of State for Home to visit that State, hear the problems of the people and solve them. Then alone can bringing the State under President's Rule be justified.

With these words, Sir, I support the Resolution.

Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। उपसभाध्यक्ष महोदय, सुदूर पूर्व के हमारे यह उत्तर पूर्व के विशिष्ट संस्कृतियों वाले राज्यों की विडम्बना ही रही है कुछ अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण और कुछ कांग्रेस दल की संकीर्ण राजनीति की नीतियों के चलते हमारे यह उत्तर पूर्व के राज्य हमारे राष्ट्र की मूल धारा से अलग-थलग रहने को शायद अभिशप्त दिखाई पड़ते हैं। हमारे सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य अभी इस बात का दावा कर रहे थे और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू करने को अपनी निष्पक्षता के प्रमाण के रूप में पेश कर रहे थे, मैं समझती हूं कि यह उनकी निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है बल्कि उनकी असफलता और निक्रमेपन का सब से बड़ा प्रमाण है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा जहां खुद सत्तारूढ़ पार्टी ने यह मांग की हो कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मणिपुर के इतिहास को अगर हम देखें तो मणिपुर को हिन्दुस्तान का स्विटज़रलैंड कहा जाता है। पता नहीं इतिहास के किसी दौर में मणिपुर में मणियां रही हों या नहीं रही हों लेकिन हमारे वर्तमान समय की सोच यह है कि मणिपुर की मणियां दिन-प्रति-दिन क्षीण होती जा रही हैं। आज हालात यह हैं कि हमारा मणिपुर हमारे उत्तर पूर्व के इन राज्यों में एक ऐसा राज्य होता चला जा रहा है जो हमारे राष्ट्र की मूल

धारा से भी अलग-थलग होता चला जा रहा है। मैं मणिपुर के इतिहास की ओर आपका और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपको याद होगा वह दिन, याद होगा वह इतिहास जब मणिपुर के पढ़े लिखे लोग, जागरूक नौजवान इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें भारत के संघ में शामिल कर लिया जाए। वह दिन आप भूले नहीं होंगे। भारत के संघ में शामिल करने के लिए जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष में उन जागरूक लोगों ने कुर्बानियां दी थी, बलिदान दिये थे। लेकिन इतनी कुर्बानियों और बलिदानों का हश्र क्या हुआ, मणिपुर के लोगों को क्या मिला, हमारी सरकार ने मणिपुर के लोगों को क्या दिया? मणिपुर के लोगों को यह मिला कि उनको वे तमाम जनतांत्रिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए जो दूसरे राज्यों को प्राप्त थे। 1949 में मणिपुर का हिन्दुस्तान में विलय हुआ। मणिपुर के लोग जो सामंती राजशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे और सामंती राजशाही के विरुद्ध लड़ते हुए यह चाहते थे कि उन्हें भी वे तमाम जनतांत्रिक अधिकार, वे तमाम विशेषाधिकार मिलें जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को प्राप्त हैं। लेकिन मणिपुर की जनता की इन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ हिन्दुस्तान की सरकार ने कौन सा सलूक किया? 1949 से 1972 तक पूरे 23 वर्षों तक मणिपुर में चुनी हुई सरकार नहीं बनी, मणिपुर में केन्द्रीय शासन कायम रहा। यह आश्चर्य की बात है कि जिस प्रदेश में राजशाही तक भी एक जनतांत्रिक संविधान के तहत काम कर रही थी उस प्रदेश को जनतांत्रिक अधिकार भी नहीं दिये गये, चुनी हुई सरकार भी नहीं दी गई। हमारे सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से आपने अभी सुना कि कांग्रेस में बुद्धि है सरकार चलाने की। शायद यही तर्क मणिपुर के लोगों को भी दिया गया कि शायद मणिपुर के लोगों में बुद्धि नहीं है वहां की सरकार को चलाने की, मणिपुर के लोगों को जनतंत्र का अनुभव नहीं है, वे इस काबिल नहीं हैं कि जनतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत रह सकें। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो तर्क साम्राज्यवादी अपनाते रहे भारत में कि भारतीयों को जनतंत्र का अनुभव नहीं है, भारतीय इस काबिल नहीं हैं कि सरकार चला सकें, प्रशासन चला सकें, जनतांत्रिक तरीके से काम कर सकें इसलिए उन्होंने भारत को यह अधिकार नहीं दिया और वही साम्राज्यवादी तर्क हम अपने मणिपुर के लोगों के साथ भी अपनाते रहे हैं। हालत यहां तक पहुंची कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने यहां तक सिफारिश कर दी कि मणिपुर को आसाम का एक ज़िला बना दिया जाए। एक स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व तक से इन्कार कर दिया। बहरहाल इस योजना पर तो अमल नहीं हुआ। लेकिन मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा 1972 तक नहीं दिया गया। हालांकि नागालैंड को 1961 में ही स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मणिपुर के जिन नेताओं ने मणिपुर की जिन पार्टियों ने भारत संघ में विलय होने के लिए संघर्ष किया था उन नेताओं में उन पार्टियों में केन्द्र सरकार के इस रवैये के चलते भयंकर निराशा पैदा हुई, भयंकर हताशा पैदा हुई और उपसभाध्यक्ष महोदय, इस राजनीति के चलते हुए मणिपुर के लोगों में एक समय के लिए यह दुर्भावनाएं भी काम करने लगी थीं कि क्या भारतीय संघ उसी औपनिवेशिक शासन का भारतीय संस्करण तो नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों में यह सवाल भी उठने लगा था कि 1949 में मणिपुर के राजा पर दबाव डालकर भारतीय संघ में विलय की जो संधि की गयी थी वह संधि मणिपुर के हित में थी या नहीं थी। जो भी हो इतिहास से सबक तो हमको लेना चाहिए। इसीलिए मैंने इतिहास के उन विस्मृत पन्नों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहा था। लेकिन वर्तमान क्या है? क्या आपने वर्तमान में अपने इतिहास से कोई सबक लिया है और अगर हम जो वर्तमान में जीते हैं, अपने इतिहास से सबक नहीं लेते तो न वर्तमान को ठीक कर सकते हैं न ही भविष्य को सही रूप दे सकते हैं और मणिपुर की हमारी विडम्बना आज यही है कि भारत सरकार ने अपने अतीत से अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 23 वर्षों के केन्द्रीय प्रशासन के काल में मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में आर्थिक विकास के नाम पर क्या कार्य किये गये? सरकारी बजट का सारा रुपया चंद ठेकेदारों, चन्द व्यवसाइयों के हाथों में इकट्ठा होता चला गया। ठेकेदार, भ्रष्ट नौकरशाह और गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ, इन तीनों की तिकड़ी मणिपुर की हालत को बिगाड़ने की वह मूल कुंजी है। इन तीनों ने मिलकर आज मणिपुर को इस हालत तक पहुंचा दिया है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि आज ये तमाम कारण मणिपुर की जनता के बीच में हताशा को जन्म दे रहे हैं। जिस प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ हो जहां सरकारी खजाने से दिये जाने वाले धन से सम्पन्न (समय की घंटी) ठेकेदारों, इंजीनियरों तथा राजनीतिज्ञों के गिरोह ने उस समाज के भ्रष्टीकरण में योगदान दिया हो जहां लोगों को रोजगार के अवसर तो पहले से ही प्राप्त नहीं थे ऊपर से जनतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जाये—मणिपुर का यह क्षेत्र आज नशीली दवाओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

है। नशीली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का जो गोल्डन क्रेसेंट है उसमें हमारा मणिपुर आज आता है और मादक द्रव्यों के तस्करों ने इस मणिपुर को मादक द्रव्यों की आवाजाही का प्रमुख केन्द्र बना दिया है। इसके चलते वे तमाम जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जो इन मादक द्रव्यों की तस्करी करते हैं उनकी तमाम समाज विरोधी गतिविधियों का केन्द्र हमारा मणिपुर बन गया है और इसके चलते आज मणिपुर में जहां एक ओर तो विभिन्न जातीय ग्रुपों में दंगे हो रहे हैं वहीं समाज का यह भष्टीकरण, मादक द्रव्यों के प्रति बढ़ती हुई रूचि भी एक बहुत बड़ा कारण है आज मणिपुर की बिगड़ती हुई स्थिति का। आज किस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियां इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके मणिपुर को अपनी साम्राज्यवादी रणनीति का एक हिस्सा बनाये हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि एक ऐसे प्रदेश में जहां सारी ऐसी स्थितियां मौजूद हों, जहां लोगों के पास रोजगार के अवसर न हों जहां भ्रष्ट प्रशासन हो, भ्रष्ट राजनेता हों, सारा का सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो वह एक ऐसी उर्वर जमीन होती है जो तमाम तरह के षडयंत्रों के लिए जमीन तैयार करती है।

मणिपुर में हमने क्या देखा? वहां कांग्रेस और मणिपुर पीपुल्स पार्टी के गठजोड़ की जो सरकार थी...(समय की घंटी) मान्यवर, थोड़ा-सा समय चाहूंगी।

उस सरकार की जनता के बीच में क्या साख रह गई थी? वह सरकार एक ऐसी भ्रष्ट सरकार थी जिस सरकार के प्रति जनता में आस्था की बात तो दूर रही खुद जो उस सरकार में जुड़े हुए थे वे ही ऐसे लोग थे आश्चर्य होगा उपसभाध्यक्ष महोदय, कि एक सरकार कैसे काम कर सकती है, एक मंत्रिमण्डल कैसे काम कर सकता है, स्वयं हमारे मंत्री जी निश्चित रूप में इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वहां एक ऐसा मंत्रिमंडल काम कर रहा था, एक ऐसी सरकार काम कर रही थी जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री की आंखों में किरकिरी की तरह चुभता था। एक मंत्री दूसरे मंत्री को फूटी आंखों से देख नहीं सकता था। जहां सरकार में जहां मंत्रिमण्डल में ऐसे ग्रुप थे, जहां खुद कांग्रेस पार्टी एक बहुगुटीय पार्टी के रूप में काम कर रही थी और जिसके मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो विभिन्न दल काम कर रहे थे वे वहां जातीय हिंसा भड़काने में पूर्ण रूप से शरीक थे। क्या ऐसी सरकार वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधार सकती थी? उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि कांग्रेस की जो साझा सरकार वहां चल रही थी उस सरकार ने मणिपुर में स्थितियों को लगातार बिगड़ते जाने दिया। हजारों लोगों के घर जला दिए गए। पहली बार सांप्रदायिक दंगे वहां पर हुए नागा-कूकियों के बीच में जो लगातार झड़पें चल रही थी, गांव के गांव जला दिए गए, जिसका जिक्र किया गया, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन मणिपुर की सरकार क्या कर रही थी मणिपुर की सरकार इन सब की मूकदर्शक बनी रही और हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने बड़ी निष्पक्षता का परिचय दिया। हमने उस सरकार को तोड़ दिया। कब उस सरकार को तोड़ दिया, जब इतनी अशांति चल रही थी और जब चारों तरफ से हाहाकार मच गया और जब आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि अब किसी बहाने आपकी सरकार नहीं चल सकती, जब खुद आपकी पार्टी के लोगों ने मांग की, जब खुद आपके मुख्य मंत्री ने मांग की, तब कहीं जाकर आपने सरकार को तोड़ा, लेकिन वह भी आधे-अधूरे रूप में, सिर्फ विधायकों की खरीद-फरोख्त से आपने सरकार का गठन किया था। आप अंतिम समय तक इस आशा में लगे हुए थे कि किसी तरह हम फिर खरीद-फरोख्त के जरिए वहां सरकार का निर्माण कर देंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसे हुआ और ठीक है आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी): आप कृपया समाप्त करें। आपने अपने समय का डबल टाइम ले लिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं समाप्त करने जा रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ऐसे प्रदेश में आपने फिर क्यों नहीं विधान सभा को भंग किया? क्या फिर भी आपके पास कोई आशा की किरण बच गई थी, क्या फिर उन्हीं दस लोगों को लेकर मणिपुर की जनता पर एक ऐसी सरकार थोप देना चाहते थे जिस पर जनता का कोई विश्वास न हो? उपसभाध्यक्ष महोदय, इस तरह का खेल आपने काश्मीर में खेला है। आपने काश्मीर में इसी तरह का खेल खेला है और आज काश्मीर में हम लोग फल भुगत रहे हैं कि तमाम तरह की साम्राज्यवादी एजेंसियां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अमरीका किस तरह वहां साजिशें कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, हमारा मणिपुर यह भी साम्राज्यवादियों के षडयंत्र का शिकार बन जाए? कृपया काश्मीर की जनता के साथ आपने जो विश्वासघात किया या जिस तरह की नीतियां अपनाई काश्मीर हमारे लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है और काश्मीर से सबक लेते हुए मैं यह कहूंगी कि हमारे इन पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिनपर, साम्राज्यवादियों की नजर पहले से गड़ी हुई है

फिर, आप एक बार ऐसा मौका न दें। यह हमारे राष्ट्र की अखंडता का सवाल है, यह हमारे देश की एकता का सवाल है, इस देश को बचाने का सवाल है और आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप यह कहते हैं कि कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, कांग्रेस को सरकार तो चलाना आता है, लेकिन कांग्रेस यह बताए कि सरकार चलाना कोई हुनर की बात नहीं है, जनता को विश्वास में लेना और जनता की समस्याओं को दूर करना, यह पहली बात होनी चाहिए और जोड़-तोड़ करके सरकार चलाना तो कोई भी चला सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अंत में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप जल्दी से जल्दी वहां मणिपुर की जनता को विश्वास में लेते हुए एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें और इस बात की कोशिश करें कि किस तरह वहां पर चुनाव करवा कर आप विधान सभा को भंग कर चुनाव करवाएं और एक ऐसी सरकार जिसपर कि वहां की जनता को विश्वास हो, ऐसी सरकार कायम करें और तमाम वे उपाय करें जिससे कि मणिपुर में जो आज अशांति कायम हुई है उस अशांति को दूर किया जा सके और मूलभूत कारणों की तलाश करते हुए इस प्रदेश को बचाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, while listening to the speeches of some of the Members belonging to the Government side, I feel more concerned. I feel that if Kashmir is one victim of the failure of the Indian statesmanship, perhaps, it is another region of the country which, at the moment, appears to the another victim of the failure of the Indian statesmanship. It has been proved once and for all, not only in India but everywhere in the world, that curtailment of democracy and repressive measures do not lead, at least permanently, to the solution of long-standing problems. If you have failed in Kashmir, if five years of Presidential rule in Kashmir has failed to bring dividends, why do you believe that suspension of the democratic process in Manipur will give you the dividends? Perhaps the Indian political leadership refuses to take lessons from its own mistakes. Therefore, as a Member belonging to the Opposition, I feel it is my duty to remind the Government not only to see reason but take lessons from its own mistakes. In the same way in which the Democratic Government was superseded in Kashmir, in the same way in which the democratic process was brought to an end, the right of the people of Manipur is sought to be taken away. They are going to be deprived of their right to have a Government of their own choice. Whether you like it or not, whether Mr. Narasimha Rao wants a man of his own party to be there or not, you cannot impose your puppet Government there. Presidential rule means a puppet administration; Presidential rule means a Government of corruption; Presidential rule means measures that lead to further confrontation. Nowhere in the country, nowhere in the country, Presidential rule has been able to give a solution to a problem. Sir, I feel that the present Government is over-dizzy with its success in Punjab. But please remember, it is not Punjab. It is not that in the same way in which you have dealt with Punjab, you can deal with Kashmir or with Manipur; it is not the same insurgency, the same ethnic conflict, the same foreign hand, the same smuggling and the same foreign interference. Sir, the failure of the Indian diplomacy is that the Government of India is not giving support to the struggle for restoration of democracy in Burma. It is not giving full-throated support because it believes that in that case, the military rulers of Burma can be of greater danger to it. But in the same way, the military rulers are giving all the help to the forces of insurgency. Therefore, the point is that the Government of India must come down to the reality and the reality is to face the situation according to the norm of democracy, according to the norm of the Constitution, according to the norm of intelligence.

Sir, another important point is this. Why has the long area been totally neglected? The people of Manipur are a victim of the economic neglect; the people of Manipur, of that region, are a

[Shri Gurudas Das Gupta]

victim of total neglect by successive governments that have ruled from Delhi. Therefore, there is a fertile soil there for insurgency and if there is a fertile soil for insurgency, you cannot just put an end to it by taking recourse to repressive measures. We plead for the economic development of Manipur; we plead for democratic measures; we plead for intelligent moves; we plead for the Government of India taking lessons from its own mistakes; we plead for the immediate restoration of democracy; we plead for an elected government in Manipur. Any further delay, any undue delay, will only give further strength and fillip to the movement of destabilisation in this part of the country. Sir, we feel that there is an attempt to weaken India. There is an attempt to weaken India, whether it is in Kashmir or it is in Punjab or it is in Manipur. There is an attempt to weaken India, and if that attempt to weaken India is to be fought, then some more intelligent measures are necessary. The Government of India is moving on the dotted line on which despotic rulers had ruled the world over. Sir, I, therefore, plead that the President's rule should be ended immediately and elections should be declared. It is the people of Manipur who can fight insurgency; it is not my friend, the Minister of State in the Government of India who can fight it. It is the people, after all; it is the aspirations of the people of Manipur, it is, after all, their solidarity with the other parts of the country, it is the goodwill, that is a more powerful weapon. Therefore, Sir, I am against the imposition of President's rule and I believe that immediate restoration of democracy will be the only way, maybe a painful way, to tackle it. And it is painful because of the stupidity of the political leadership. The country will have to pay a price for this stupidity of the political leaders. We are paying a price for their stupidity. It is, therefore, painful. It is bound ot prolong. It is bound to be definitely costly. There cannot be any other shortcut. Therefore, I plead for the restoration of democratic process in Manipur.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to speak. Sir, there are two aspects of this matter which I would like to Place before this august House. One is, the Government had invoked Article 356 to impose President's rule, and also, the State legislature is kept under suspended animation. I do not know what the thinking of the Government is. Are they going to dismiss the State legislature? Are they going to order holding of fresh elections? What is the thinking of the Government? The Home Minister should have to explain it before the House. Sir, we have always been opposing the invocation of Article 356. Article 356 runs counter to the very spirit of the Constitution. Our Constitution is a Federal Constitution and the Central Government is using Article 356, many a time misusing it. And in this particular case, the Central Government has absued this Article 356 to impose its rule on a State Government. On a number of occasions it has used this Article. The Home Minister or the Government of India might have lost count how many times they had used this Article for dismissing various State Governments, duly and democratically elected by the people. Sir, in this particular case, the ethnic conflict between the Kukis and the Nagas is not a new affair. It has been going on in Manipur for the last two years, maybe, for the last one year it has become serious. This is an unending problem. Whichever party formed the Government was there, could was not be able to control it. Even the Central Government has not bestowed sufficient attention on finding a solution to this problem. I am not going into details due to ethnic strife a number of Kukis were killed, a number of Nagas were killed, their villages were burnt and the Nagas' burnt Kuki villages. This has been going on for the last, say, one year. Why had the Government dragged its feet so far in

intervening and rectifying the situation? Mr. Rajesh Pilot, Minister of State for Internal Security, had visited Manipur a number of times and he had taken one view. The Home Minister, Mr. Chavan, had taken another view. It appears there are some differences of opinion between the Minister of Home Affairs and the Minister of State for Home Affairs. It appeared in the press. What ultimately made the Government to impose the President's rule right now? How could they choose this timing? What are the reasons for this timing? Mr. Narayanasamy just now said that as far as imposing President's rule was concerned, the Central Government led by Mr. P.V. Narasimha Rao is neutral. The Government have imposed President's rule on States ruled by the Opposition parties. In this particular instance, they have imposed the President's rule on their own Government. Why? What are the reasons?Is it really true?

Sir, this Government of Manipur is a coalition Government led by the Congress (I) party. One of the coalition partners had given directives on November 18 and December 9. All Naga Ministers and MLAs were asked to resign immediately and condemn the Central Government and the State Government for helping and aiding the kuki terrorists against the Nagas. The date by which the Naga MLAs were asked to resign was December 31. There were 11 Naga MLAs in the 60-member State Assembly, of whom four were Ministers including the former Deputy Chief Minister, Mr. Rishang Keishing. Any way, this coalition Government is deemed to fall because of their internal contradictions. The elections are coming within a year. Meanwhile, the Central Government wanted to intervene and dismiss the State Government and wanted to get mileage out of this confusion in the coming election. That is the motive behind imposing Present's rule. That is the reason for chosing this particular time to intervene by the Central Government. Therefore, Sir, I suspect the motive of the Central Government. I suspect the motive of the Union Government because they are using it at a critical situation which is obtaining in Manipur for their own partisan and political end. This is really most unfortunate. This will not be in the best interest of the country. In the beginning itself I have stated that we, as a party, are against imposition of President's rule on any State. In this particular instance, the situation is difficult. There is tremendous law and order problem. The Government's motive in imposing President's rule at this particular point of time is suspect. Therefore, I would like to ask the Government to come out in the open. Are they going to suspend the Assembly? Are they going to dissolve the Assembly? Are they going in for fresh elections within six months not waiting till 1995? What is the Government? The Government have to explain to the nation why they have taken this decision at this particular point of time ignoring all the while the ethnic conflict, the ethnic strife and the tremendous law and order problem which is obtaining there. With these few words I conclude.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I am reminded of a world used by Mr. Shinde, the main speaker on the side of the ruling party. Regarding Manipur, he used the term 'sarvadharmasamanvay', something like that. Really the report submitted by the Governor to the President makes it amply clear how that type of a Government came into being in Manipur in the first instance. The party position has been stated by the General in a brutally frank manner, that is, in the present Congress (I) led coalition Governmentr in Manipur the party position is Congress (I) 13, Manipur People's Party 11, Janata Dal defected to, Congress (s) 3, Congress (s) defected 3, Manipur Congress 7, unattached 6, National People's Party 1 and Kuki National Assembly defected. Such a

[Prof. Saurin Bhattacharya]

mosaic of diverse and opposite political parties would be hardly found in any part of the country and by that very token it could be said that the Congress (I) could really achieve the central position of our country, that is, unity in diversity. The formation of such a Government is itself a feat which is perhaps unparalleled in our Indian history. This is the Government regarding which the Governor's statement says that there is a reigning Chief Minister, a Deputy Chief Minister who was again a former Chief Minister and another former Chief Minister, all were acting at cross purpose and in doing so were really collaborating with the underground extremists or insurgents, whether Nagas of different varieties or Kukies or Meitis, none excluded. Even the Chief Minister of the neighbouring State of Nagaland has received due attention of the Governor. Mr. S.C. Jamir is certified to be firmly in saddle. But the dispute with the influential group of Seamars posed a problem and he continues to keep contacts with the NSCN (K). So, with this political picture, in which the principal role has been played by the Congress (I), it is very difficult to expect from the Central Congress (I) Government, which was dragging its feet to impose the President's rule, any good intention. The question is: the Assembly has been kept in suspended animation. To use the language of the Governor, what for? In his report he castigates the total political leadership comprising the Manipuir Assmebly. So to what expectation that Assembly has been kept in suspended animation, herein comes the question of some *mala fides* on the part of the Congress (I) Governament and even of the Governor who otherwise presented a very objective report to the President. Such a situation precludes really any action within the framework of the present Assembly. The only alternative would be a new Assembly election. But that would amount to whether a different picture would emerge or not. It will be decided by the actual events. But perhaps, there is no other way out of this mess created by the Congress set up in the North East. Therefore, I would urge upon the Central Government to dissolve the Assembly as a forthright step. The Governor, in his Report has referred to the insurgent situation, the uncertain situation, prevailing in Manipur and other areas of the North-Eastern States and has further stated that because of the lack of effective economic and social measures, the people have become alienated. So, the question that comes up is: what steps are being taken in that direction? At least, a fresh election may be expected to give answers to these questions; I mean, an attempt in that direction is unavoidable. The way President's Rule was imposed establishes not only the *mala fide* behaviour on the part of the political leadership in Manipur but also its criminal liability thus impeding the entire development of the country. In that situation, President's Rule was the minimum that could be done. What is now necessary is to take into custody all these politicians who were involved, and who are still involved, with these so-called extremist parties, whether Nagas or Kukis or Meities, of that area.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Vizol, you are the last speaker. Your party was allotted seven minutes but your party Member had already consumed all the seven minutes. So, I would request you to conclude in five minutes.

SHRI VIZOL (Nagaland): Mr. Vice-Chairman, Sir, speaking about the imposition of President's Rule in Manipur, I would say that I am totally opposed to it under any circumstances. I am against the practice of keeping a democratically elected Government, anywhere in the country, under suspended animation. It hits my conscience, it pricks my conscience.

I cannot accept it. I have seen enough

of it. India, in spite of being considered the largest democracy in the world, has been continuing this practice for ages. There has been no time when President's Rule was not imposed in one State or the other, either in the North or in the West or in the South. What a shame! Is it that the elected Members of Parliament or of the State Assemblies are incapable of handling the situation by themselves? I think it is best that of the Centre interferes the least. I am opposed to the imposition of President's Rule in principle. I am not going to speak about the merits or demerits of the President's Rule in our State. But I would like to say something about how it originated this part of the country. You know that on 24th December, 1992 a gentleman came to Delhi. This gentleman is the Chairman of the Kukis National Organisation... who is also the Commander-in-Chief of the Kuki National Army. In full military uniform, he came to Delhi, met some Central leaders. He was asked to meet the then Chief of the Indian Army, Gen. Rodrigues. He met Gen. Rodrigues on 24th December at Delhi. On that day, he was very happy. He was accorded a warm welcome, according to my information. He was very happy. After this he went home. He organised the Kuki Army, equipped them with sophisticated weapons. I cannot say how powerful he became so soon. Nobody could say. He took control of the situation and expelled in a criminal way all non-Kukis residing in that area including the Nagas. So, the Nagas started killing the Kukis in the Naga-dominated areas. That is how it all started. All this started in the full knowledge of the Centre, with the help and support of the State Government. This is our own making. Are we not ashamed of it. We must know the history and the origin of this organisation. We are exposing ourselves to the world outside. This is the thing. I will come to this at some other point of time during this Session. Today I will make a short speech. I want to inform the House in brief.

Now, the President's rule is imposed. Election is due only in January, 1995. Since the Assembly is under suspension, there may be a lot of horsetrading. I am not a businessman. But I learn that in trade-not only in horse-trade but in other trades also money is used, power is used. That is how of corruption starts. This money and power transaction is the cause of defection. In our dialect, defection means *bastardisation*. It is a very shameful word. Today you can defect and get a berth in the Ministry. Defectors have come to be considered the best politician by our innocent voters. You defect from your party and go to another party. Get a berth in the Ministry and get introduced in the House. I cannot tolerate it. It is against my conscience, a degradation of human values.

We have the anti-defection law., But who is caring for this law? It is misused and abused. Why not we have a blanket ban? A total ban on defection....?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): You please conclude now. You please conclude now.

SHRI VIZOL: Why not we have a blanket ban on defections? This degrades public life. This degrades all of us. We are all defectors. Well, Mr. Vice-Chairman, election could be held even before the due date in Manipur State. Today, this Resolution is going to be adopted. However much I may oppose or he may oppose or he may oppose, this Resolution is going to get through. But, for goodness sake, do not extend the President's Rule. Elections could be held even before the due date. And let the State have a democratically elected Government, whatsoever party may come to power.

With these words, Sir, I again thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now the Minister.

SHRI P.M. SAYEED: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to all those

[Shri P.M. Sayeed]

hon. Members who have participated in the discussion on the Resolution. Sir, I have been hearing from all sections of the House. Barring one or two persons or parties, all others have supported the imposition of President's Rule in Manipur. Sir, the Governor's Report which is made available to all the Members gives in detail what was happening in Manipur. Sir, in this Report, in the second para, the Governor has given the parties' strength and also in a greater detail the insurgent activities, the Naga-Kuki conflict and the Metei ethnic problems. And the Governor, therefore, was compelled to come to the conclusion that there was no other alternative but to impose President's Rule in Manipur.

Sir, Mrs. Sushma Swaraj was very vocal. She was also mentioning that her Party itself demanded the President's Rule. Her only opposition is why the Assembly is kept under suspended animation. I will come to that, Sir, later on. What I want to mention are the figures which were provided in the reports of the Manipur Government, the figures for the period 1992-93 and 1993-94 about the persons killed in Naga-Kuki clashes and by insurgent groups, NSCN and Metei extremist organisations in Manipur. This is as per the verified report. In 1990-93, the Naga-Kuki total killings were 305, the Metei extremist killings were 160, and the NSCN killings were 126. And the type of Government, as you know, was a coalition Government. The Government was ineffective to control these insurgents, and the violent activities were increasing. Therefore, there was no other alternative for the Government of India but to impose President's Rule.

Sir, there were allegations that the Assembly is kept under suspended animation in order to give an advantageous position to the Congress Party before the next election. Sir, 16 months are still left in the Assembly's life. In any case...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Minister, as it is already 5 o'clock, I have to take the sence of the House. You are on your legs.

5.00 P.M.

I think within ten or fifteen minutes, this Resolution could be got through. If the House agrees, we will finish it today.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मैं सईद साहब से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि लम्बा भाषण न दें।

श्री पी०एम० सईद: मैं लम्बा भाषण नही दूंगा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कहां जाना है (व्यवधान) इफ्तार पर जाना है(व्यवधान)

श्री पी०एम० सईद: मैं दो तीन प्वाईंट बता कर के खत्म करूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने सस्पेंडेड एनिमेशन का बताया। यह एक आर्गुमेंट दिया कि 16 महीने बचे थे फिर हमारी सरकार को तो ढाई ढाई साल बचे थे। यह तो कोई वेलिड आर्गुमेंट नहीं है। यह कोई वेलिड आर्गुमेंट नहीं है कि 16 महीने बचे थे (व्यवधान)

श्री पी०एम० सईद: यह नहीं है, मैं बता रहा हूं, यह रीज़न नहीं है (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : आपकी सरकार क्यों गई यह आपको खुद मालूम है (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने खुद सुनाया कि एक जगह 350 मरे (व्यवधान) एक जगह 126 मरे मगर हमारे यहां तो कोई परिंदा भी नहीं फटका था, एक चिड़िया भी नहीं मरी थी (व्यवधान) यह कोई तर्क नहीं है। अगर देना है तो कोई वेलिड आर्गुमेंट दीजिये। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद: मैं दे रहा हूं। सुषमा जी, आप मुझे दो मिनट दे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): आप बोलिये।

SHRI P.M. SAYEED: We have already completed five years of President's Rule in Kashmir. Now all the parties in Kashmir are trying to find a method by which political process could be started in Kashmir. What I want to say is that in the North-Eastern region,

we cannot take it lightly. So, a situation should not be allowed to develop whereby political process may be difficult in future. Therefore, the Government thought it fit to keep it under suspended animation. The Coalition was headed by the Congress Party. If we find that it is not feasible or practicable, we do not mind even dissolving the Assembly. But, at the same time, we should not put an end to it. That is the only purpose why the Government kept it under suspended animation.

श्रीमती सुषमा स्वराज: कांग्रेस की सरकार है इसलिए (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: उन्होंने कोई बाबरी मस्जिद थोड़े तोड़ी थी (व्यवधान)

SHRI P.M. SAYEED: Sushmaji said that for 99 times the Government imposed President's Rule in the country. That is not correct.

It is only for 91 times.

श्रीमती सुषमा स्वराज: 91 और 99 में बहुत बड़ा अंतर है। I stand corrected.

SHRI SHSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I am on a point of order. Whether it is for 91 times or 99 times, does it include the period of 1977 to 1980 when Janata Party was there or is it only during the Congress Government period?

SHRI P.M. SAYEED: No, it includes that period also. But I do not want to point any accusing finger at any party, much less Sushmaji's party. What I want to say is about the problem in the North-Eastern region. I am also coming from a far-flung area. Now you are sending money to them but at the same time you have to honour their ego, their tribal culture and their identity.

Time and again, in this very House certain things are said. Even today, somebody was saying that English was a foreign language. Some of the Members do not know that English is the official language in some States. For example, the official language in Nagaland is English. This sort of thing raises some doubts in the minds of the people of the North-Eastern States.

Therefore, we will have not only to take care of the socio-economic development of the region. Their cultural identity, their language, there heritage, every-thing, has to be taken care of. I am not accusing anybody.

अब ऐसा कहना कि क्या जरूरत है। मैंने आपको कुछ बताया। आपको एलेज नहीं किया। मैं यह कह रहा था उनके बारे में कि नार्थ इस्टर्न के जो लोग है उनको कोई भी बाहर से चाहे उनके पड़ोसी हों या दूर के बाहर से हो या अंदर से हो, किसी तरह से हथियार देकर इस देश की एकता और अखंडता पर कोई हरकत करेंगे तो भारत सरकार किसी भी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ हमें यह करना है कि उनका जो ट्राइबल कैरेक्टर है उनका इक्नामिक डेवलपमेंट है इस सबको मद्देनजर रखते हुए उनको डेवलपमेंट देना है।

It is only for this purpose that we are keeping the Assembly under suspended animation.

Sir, many points have been made. If I have to refer to all these points, one by one, it would take a lot of time. However, there are one or two points I would like to refer to. My good friend, Mr. Gurudas Das Gupta, made one point.

SHRI V. NARAYANASAMY: He never raised any point.

SHRI P.M. SAYEED: I agree with him that imposition of President's rule is not the answer to insurgency. To meet insurgency, we have to have an integrated plan. Such a plan is on. We will see that this plan is on till insurgency is totally wiped out.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: What about election?

SHRI P.M. SAYEED: Sir, I would be failing in my duty if I do not refer to one fact. After imposition of President's rule the situation has improved. The Janata Dal Member, Mr. Kulabidhu Singh, himself had mentioned it. There has been a twenty per cent reduction in the

[Shri P.M. Sayyed]
killings. He himself had agreed. There is a remarkable improvement in the situation. Violence and killings have come down. Not only that. In many districts, doctors are attending to their duties. Engineers are attending to their duties. Offices are functioning. Work is going on in a normal manner. Therefore, improvement is there. We hope that further improvement would be there.

Mr. Padmanabham, one of my intimate friends, asked whether the Government was prepared to talk to the insurgents. I want to convey to this august House that the Government is prepared to talk to anybody, provided they eschew violence, provided they accept the Constitution of India. We are prepared to talk to, we are prepared to have a dialogue with, anybody; even with the insurgents, for that matter.

Sir, I do not want to take more time. I would request the hon. House...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the hon. Minister has yielded. I want to put a simple question. The Assembly has been kept under suspended animation. Therefore, I would like to get a categorical assurance from the hon. Minister, who represents the Government, that the possibility of holding early elections would be explored to meet the democratic aspirations of the people of Manipur. Would he give this assurance to the House?

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: That was my question also.

SHRI P.M. SAYEED: I would like to draw the attention of Mr. Gurudas Das Gupta to the last but one paragraph of the Governor's report. You may not have gone through that report. It says: "A period of cooling off will not only minimise the influence of the political leaders with questionable antecedents, it may also help in encouraging alternative and better leadership to emerge." Your own point I have elaborated. (*Interruptions*). Therefore, what I want to convey... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now I shall put the Statutory Resolution to vote.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Has he completed his reply?

SHRI P.M. SAYEED: I appeal to the House to unanimously adopt this Resolution. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now I put the Statutory Resolution to vote. The Minister has replied. He has explained the position. The question is:

> That this House approves the Proclamation issued by the President on the 31st December, 1993, under article 356 of the Constitutions in relation to the State of Manipur.

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 23rd February, 1994.

MGIPCBE—CRC—1 RSS/ND/95—1-2-96—400 Copies